

विचार-प्रवाह...

खेती-किसानी का स्वरूप



देहरादून, बुधवार, 30 सितंबर 2020

पेज 3



AGE
P3
PUBLICATION



मौसम

अधिकतम न्यूनतम
31.0° 21.0°

37244.59

2

मिसाइल हमला करवा सकते हैं ट्रंप

7

एक कप्तान जो सब पर भारी

नई एप्रोच से नमामि गंगे में मिली सफलता



अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर फोकस

प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा के निकटवर्ती पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर फोकस किया जा रहा है। यहां जैविक खेती और औषधीय पौधों की खेती की योजना है। आर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। मिशन डॉल्फिन से डॉल्फिन संवर्धन में मदद मिलेगी।

संवाददाता

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे के अंतर्गत उत्तराखण्ड में 521 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं के शुरू होने से उत्तराखण्ड से अब प्रतिदिन 15.2 करोड़ लीटर दूषित पानी गंगा नदी में नहीं बहेगा।

लोकार्पित किए गए प्रोजेक्ट में जगजीतपुर हरिद्वार में 230 करोड़ रुपये की लागत से बना 68 एमएलडी क्षमता का एसटीपी, 20 करोड़ की लागत से बना 27 एमएलडी क्षमता का अपग्रेडेड एसटीपी, सराय हरिद्वार में 13 करोड़ की लागत से बना 18 एमएलडी क्षमता का अपग्रेडेड एसटीपी, चंडी घाट हरिद्वार में गंगा के संरक्षण और जैव विविधता को प्रदर्शित करता 'गंगा संग्रहालय', लक्कड़ घाट, ऋषिकेश में 158 करोड़ की लागत से बना

प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे के अंतर्गत उत्तराखण्ड में 521 करोड़ की आठ परियोजनाओं का लोकार्पण किया

■ पीएम मोदी ने परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया

26 एमएलडी क्षमता का एसटीपी, चंद्रेश्वर नगर-मुनि की रेती में 41 करोड़ की लागत से बना 7.5 एमएलडी क्षमता का एसटीपी, चोरपानी, मुनि की रेती में 39 करोड़ की लागत से बना 5 एमएलडी क्षमता का एसटीपी और बद्रीनाथ में 19 करोड़ की लागत से बना 1.01 एमएलडी क्षमता का एसटीपी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने रोविंग डाउन द गंगेज व ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए बनाई गई मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के प्रतीक चिह्न का भी अनावरण किया।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखण्डवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मां

जल जीवन मिशन में उत्तराखण्ड सरकार एक कदम आगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी की महत्ता को माता-बहनों से अधिक कौन समझ सकता है। हमने जल से जुड़े मंत्रालयों को एक कर जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया। जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल का लक्ष्य लिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है। उन्होंने केवल एक रूपए में पानी का कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है। वर्ष 2022 तक हर घर नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखण्ड में कोरोना काल में भी पिछले 4-5 माह में 50 हजार परिवारों को पानी का कनेक्शन दिया गया है जो कि उत्तराखण्ड सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

गंगा हमारे सांस्कृतिक वैभव और आस्था से तो जुड़ी ही है, साथ ही लगभग आधी आबादी को आर्थिक रूप से समृद्ध भी करती है। नमामि गंगे मिशन, नई सोच और नई एप्रोच के साथ शुरू किया गया। यह देश का सबसे बड़ा नदी संरक्षण अभियान है। इसमें समन्वित रूप से काम किए गए। गंगा जी में

गंगा पानी गिरने से रोकने के लिए एसटीपी का निर्माण किया गया है। अगले 15 वर्षों की आवश्यकता के अनुसार एसटीपी की क्षमता रखी गई, गंगा के किनारे लगभग 100 शहरों और 5 हजार गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया है और गंगा की सहायक नदियों को भी प्रदूषण से

उत्तराखण्ड में 6 साल में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता चार गुना हुई

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में नमामि गंगे के अंतर्गत लगभग सभी प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। राज्य में 6 साल में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता को 4 गुना कर दिया गया है। लगभग सभी नालों को टैप कर दिया गया है। इनमें चंद्रेश्वर नाला भी शामिल है। यहां देश का पहला 4 मंजिला एसटीपी शुरू हो चुका है। अगले वर्ष हरिद्वार कुम्भ मेले में श्रद्धालु गंगा की निर्मलता का अनुभव लेंगे। सैकड़ों घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। साथ ही रिवर फ्रंट भी बनकर तैयार है। गंगा म्यूजियम से हरिद्वार आने वाले लोग गंगा से जुड़ी विरासत को समझ पाएंगे।

मुक्त रखने का काम किया जा रहा है। (विस्तृत खबर पेज 8 पर...)

संक्षिप्त समाचार

हाथरस की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की दिल्ली में मौत एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) हाथरस। सामूहिक दुष्कर्म के बाद 19 वर्षीया युवती के साथ अमानवीय कृत्य से हाथरस शर्मसार है। सामूहिक दुष्कर्म की इस घटना को निभया पार्ट-2 का नाम दिया गया है। हाथरस में 14 सितंबर को सामूहिक दुष्कर्म के बाद अमानवीय कृत्य झेलने वाली पीड़िता का संघर्ष मंगलवार को नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में समाप्त हो गया। मायावती का ऐलान लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) पटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने यूपीए से नाता तोड़ दिया है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है। बिहार चुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा ने अब बीएसपी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ मिलकर गठबंधन करने की घोषणा की है। मायावती ने भी इस पर मुहर लगा दी है।

अगस्त तक हर 15वां शख्स चीन के नए पैतरे पर कोरोना की चपेट में था भारत का दो टूक जवाब

खुलासा: आईसीएमआर ने राज्य सरकारों को किया आगाह एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोरोना वायरस के लगभग 61 लाख मामले सामने आए हैं। इनमें से 9 लाख से ज्यादा केस अब भी ऐक्टिव हैं। देश में कोविड-19 के चलते अबतक 96,318 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि सीरो सर्वे की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक देश की एक बड़ी आबादी अब भी कोरोना वायरस की जद में आ सकती है। डीजी आईसीएमआर बलराम भार्गव ने बताया कि आईसीएमआर की दूसरी नैशनल सीरो रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2020 तक 10 साल से ज्यादा की उम्र का हर 15वां शख्स कोरोना की चपेट में आ चुका है। देश में कोरोना को लेकर पैदा हुए हालात और वर्तमान स्थिति की जानकारी देने के लिए केंद्रीय

टंड में कोरोना बरपायेगा कहर

डीजी आईसीएमआर ने राज्य सरकारों से अपील की है कि आगामी त्योहारी सीजन, सर्दी के मौसम को देखते हुए वे खास सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा, अगले कुछ महीनों के दौरान कई बड़े त्योहार, सर्दी के मौसम और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की आशंका के मद्देनजर राज्य सरकारों को नई कंटेनमेंट स्ट्रेटिजी को अपनाना होगा। पहले सीरो सर्वे में देश की .73 फीसदी आबादी में कोरोना संक्रमण का अनुमान था, अब यह 7.1 फीसदी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और नीति आयोग ने मंगलवार को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजी आईसीएमआर बलराम भार्गव ने कहा, सीरो रिपोर्ट में एक बड़ी आबादी के कोरोना की चपेट में आने की आशंका जताई गई है, ऐसे में 5टी स्ट्रेटिजी (टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट और टेक्नॉलजी) को अपनाना होगा। उन्होंने कहा, दूसरी सीरो रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त तक 10 साल से ऊपर का हर 15वां शख्स कोरोना की चपेट में आ चुका है। सरकार के पास कोरोना

वैक्सिन के लिए 80,000 करोड़ रुपये के बजट पर बोला स्वास्थ्य मंत्रालय, 80 हजार करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी या नहीं अभी स्पष्ट नहीं है।

भारत सरकार ने वैक्सिन को लेकर डॉ. पॉल की अध्यक्षता में कमिटी बनाई है। इसमें वैक्सिन को लेकर लोगों को प्राथमिकता देने पर चर्चा हुई है। बजट का भी अनुमान लगाया गया है। हमारे पास पर्याप्त राशि है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में 6 कंपनियों रेमिडेसिवीर का निर्माण कर रही हैं।

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। चीन ने एक बार फिर अपनी बात से मुकरते हुए एलएसी के मसले पर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। इसपर भारत ने पलटवार करते हुए चीन से सख्त अंदाज में कहा कि बार-बार भटकाने की मंशा सफल नहीं होगी। बता दें कि चीन ने कहा था कि वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं देता है और इस इलाके में भारत की ओर से किये जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम का विरोध करता है। चीन ने एक बार फिर एलएसी को तय करने में 1959 के एकतरफा समझौते का हवाला दे रहा है।

दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर चीन के दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि भारत ने कभी भी 1959 के चीन के एकतरफा तौर पर तय एलएसी को नहीं माना। 1993 के बाद ऐसे कई समझौते हुए जिसका मकसद अंतिम समझौते तक सीमा पर शांति

पलटवार

■ 61 साल पुरानी एलएसी की परिभाषा को मानने से किया इनकार

और यथास्थिति बनाए रखना था। भारत ने जतायी प्रतिबद्धता: वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि 2005 भारत सीमा के निपटारे के लिए राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर समझौता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और चीन दोनों ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एक आम समझ तक पहुंचने के लिए एलएसी के स्पष्टीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

चीन का बयान आपत्तिजनक: विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कभी भी 1959 के चीन की ओर एलएसी की एकतरफा दी गयी परिभाषा को स्वीकार किया।

भारत ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में चीन का इस तरह का बयान आपत्तिजनक है और दोनों देशों के बीच आपसी सहमति का घोर उल्लंघन भी है।

चीन ने लद्दाख को मान्यता देने से फिर किया इनकार

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

पेइचिंग। चीन ने एक बार फिर भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता देने से इनकार किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि भारत ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना अवैध तरीके से की है। वे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल

जंग कर खाद्य संकट को छिपा रहे जिनपिंग

कंट्रोल को लेकर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। हम 7 नवंबर 1959 को बताई गई सीमा को एलएसी मानते हैं। जानिए आखिर क्यों चीन बार-बार साल 1959 का उल्लेख करते हुए मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार करता है। कोरोना वायरस के कारण चीन

में खाद्यान्न संकट गहराता जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2013 के क्लिन योर प्लेट अभियान को फिर से लॉन्च किया है।

पश्चिमी मीडिया का भी मानना है कि चीनी प्रशासन इस योजना की आड़ में देश में पैदा हुए खाद्य संकट को छिपा रहा है।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development

All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding

1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation

A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Gadoli Media Ventures

Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

Contact: